हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

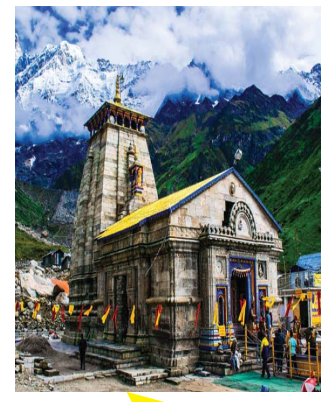

वर्ष:5 अंक:50 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, मंगलवार, 24 फरवरी 2026

देवसंस्कृति विश्वविद्यालय तपोभूमि, लघु भारत का स्वरूपः सांसद त्रिवेंद्र रावत

देवसंस्कृति विवि में एनएसएस राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का भव्य आगाज़

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता के रंगों से सराबोर हो उठा, जब राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का भव्य शुभारम्भ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शिविर में देश के 13 राज्यों और 185 विश्वविद्यालयों से आए एक हजार से अधिक युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवाओं ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का सजीव चित्र प्रस्तुत किया। पूरा परिसर 'लघु भारत' की अनुभूति कराता नजर आया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देवसंस्कृति विश्वविद्यालय त्याग, तपस्या और साधना की तपोभूमि है। यहां विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए

एनएसएस के छात्र-छात्राएं भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में तीव्र औद्योगिकीकरण हो रहा है, सीमाओं तक सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है और सेना अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। उन्होंने कहा कि आज भारत सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से बढ़ा है। कोरोना संक्रमण काल की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने न केवल महामारी से पार पाया, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाए रखा। पिछले वर्षों में भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और युवा पीढ़ी को स्वयं को निरंतर अपडेट रखने की आवश्यकता है।

उन्होंने भारतीय वैदिक और सनातन सांस्कृतिक परंपरा को राष्ट्र की शक्ति बताते हुए कहा कि यह संस्कृति निरंतर प्रवाहित रही है और इसी ने देश को संघर्षों के बीच भी सशक्त बनाए रखा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय एकीकरण शिविर युवाओं में राष्ट्रभाव और सांस्कृतिक समरसता को और मजबूत करेगा।

'युवा शक्ति ही विकसित भारत की आधारशिला' - रेखा आर्या

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज का भारत युवा भारत है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प युवाओं के परिश्रम, नवाचार और राष्ट्रनिष्ठा से ही पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सच्चा युवा वही है जिसके विचार पवित्र हों, लक्ष्य स्पष्ट हो और कर्म में निष्ठा हो। भारतीय युवाओं की प्रतिभा को आज वैश्विक मंच पर सम्मान मिल रहा है। स्टार्टअप, विज्ञान, तकनीक और खेल के क्षेत्र में युवाओं ने भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण शिविर केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि 'विविधता में एकता' की भावना को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम है। ऐसे शिविर युवाओं में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करते हैं।

शौर्य दीवार पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि

कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित शौर्य दीवार पर पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या ने की। इस अवसर पर समरदीप सक्सेना, शांतिकुंज के व्यवस्थापक योगेंद्र गिरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

एक नजर

तेजस विमान में तकनीकी खराबी आई थी, दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआः एच ए एल

नयी दिल्ली। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने वायु सेना के एक स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के इस महीने के शुरू में दुर्घटनाग्रस्त होने की रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा है कि इस विमान को तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा था और उसे किसी भी तेजस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना नहीं है। वायु सेना के लिए तेजस बनाने वाले उपक्रम एचएएल ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने तथा तेजस विमानों की उडान रोके जाने की मीडिया में आई रिपोर्टों पर सोमवार को स्पष्टीकरण दिया। एच ए एल ने कहा कि एलसीए तेजस के किसी भी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई सूचना नहीं है। सार्वजनिक उपक्रम ने कहा कि जिस घटना का मीडिया में हवाला दिया जा रहा है वह ज़मीन पर हुई एक मामूली तकनीकी समस्या थी। सार्वजनिक उपक्रम ने कहा है कि तेजस का समकालीन लड़ाकू विमानों में विश्व में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड है और वह इसे बनाये हुए है। एचएएल ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत इस मुद्दे का गहन विश्लेषण किया जा रहा है और एचएएल त्वरित समाधान के लिए वायु सेना के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ताजा घटना इस महीने के शुरू में वायु सेना के एक प्रमुख एयर बेस पर उस समय हुई जब यह विमान नियमित प्रशिक्षण उडान के बाद रनवे पर उतर रहा था। दुर्घटना में पायलट समय रहते पैराशूट की मदद से बच निकलने में सफल रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तेजस की तीसरी बड़ी दुर्घटना है पहला तेजस जैसलमेर में एक फायरपावर में हिस्सा लेने के बाद लौटते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस घटना में भी पायलट पैराशूट की मदद से बच निकला था। दूसरी बड़ी दुर्घटना पिछले वर्ष नवम्बर में दुबई एयर शो में उस समय हुई जब तेजस विमान अपनी करतबबाजी दिखा रहा था। इस दुर्घटना में पायलट की भी मौत हो गयी थी। इस घटना की जांच की जा रही है।

तेजस वायु सेना के लिए देश में ही बनाया गया पहला लड़ाकू विमान है। वायु सेना के लिए तेजस के उन्नत संस्करण तेजस मार्क -1 ए के 180 विमानों की खरीद के संबंध में एच ए एल के साथ एक अनुबंध किया गया है। इन विमानों की डिलीवरी की कई समय सीमा पहले ही जा चुकी हैं लेकिन अभी वायु सेना के लिए ये विमान मिलने शुरू नहीं हुए हैं।

सोने की कीमतों में तेजी विश्व भर के केंद्रीय बैंकों की खरीद के चलतेः सीतारमण

नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सोने की कीमतों में इस समय चल रही तेजी मुख्य रूप से दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने-चांदी की खरीद बढ़ाये जाने के कारण है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश में सोने के निवेश और उपभोग मांग को देख कर ऐसा नहीं लगता कि स्थिति चिंता के स्तर पर है फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की बाजार पर निगाह बनी हुई है। श्रीमती सीतारमण आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बजट पश्चात बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रही थी।

वित्त मंत्री ने कहा, 'आजकल अधिकांश देश, विशेष रूप से उनके केंद्रीय बैंक, सोना और चांदी खरीदकर भंडारित कर रहे हैं। जब आप भारतीय उपभोक्ता बाजार की बात करते हैं, तो यह एक प्रवृत्ति के रूप में दिखता है। हर केंद्रीय बैंक के पास कुछ न कुछ भंडार होता है, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कई अन्य देशों के केंद्रीय बैंक भी सोना खरीद रहे हैं।' उन्होंने कहा, ' कीमतों में जो उछाल आया है, वह मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों

द्वारा सोना खरीदने और उसे संग्रहित करने के कारण है। सीतारमण ने घरेलू उपभोग के बारे में कहा कि यह हर मौसम और हर त्योहार के साथ जुड़ी एक सामान्य स्थिति रहती है। लेकिन सोनेऔर चांदी की वैश्विक कीमतों में जो असामान्य और सामान्य उतार-चढ़ाव से कहीं अधिक वृद्धि हुई है, उसका प्रभाव हर घरेलू खरीद पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा , ' कीमती धातुओं के मामले में हमारी निर्भरता लगभग पूरी तरह बाहरी स्रोतों पर है। हमारे पास सोने की खोज और उसके खनन का पर्याप्त घरेलू स्रोत नहीं है। इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वे हमारी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में सोना हमेशा से परिवारों के लिए एक पसंदीदा निवेश रहा है। घरेलू उपभोग की उच्च मांग में त्योहारों के मौसम के दौरान मौसमी उछाल भी देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, ' हम इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह किसी चिंताजनक स्तर तक पहुंचा है। मेरा मानना है कि यह एक निश्चित सीमा से आगे नहीं गया है।

हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक भी इस पर निगरानी रखे हुए है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस वर्ष अप्रैल- दिसंबर 2025 तक के स्वर्ण आयात के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें एक साल पहले की तुलना में मूल्य के हिसाब से कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में सोने का आयात 1.83 प्रतिशत 49.39 अरब डॉलर के बराबर रहा जो इससे पिछले साल इसी अवधि में 48.51अरब डालर के बराबर था। इस दौरान सोने के आयात की मात्रा 18.29 प्रतिशत घटकर 5,22,380 किलोग्राम रह गई।

भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी

नयी दिल्ली। भारत ने ईरान में निरंतर बदल रही स्थिति को देखते हुए वहां रह रहे भारतीय नागरिकों (छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यवसायियों और पर्यटकों) को वाणिज्यिक उड़ानों सहित सभी उपलब्ध परिवहन साधनों के माध्यम से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को एक परामर्श जारी कर कहा है कि इस वर्ष पांच जनवरी को जारी परामर्श के क्रम तथा ईरान में विकसित हो रही स्थिति को देखते हुए ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों (छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यवसायियों और पर्यटकों) को उपलब्ध परिवहन साधनों, जिनमें वाणिज्यिक उड़ानें भी शामिल हैं, के माध्यम से ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने 14 जनवरी को जारी परामर्श को दोहराते हुए कहा है कि सभी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरतें, विरोध प्रदर्शनों या धरनों वाले क्षेत्रों से दूर रहें, ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें तथा किसी भी नए

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS
सत्यमेव जयते

घटनाक्रम के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें। परामर्श में कहा गया है कि ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने यात्रा और आव्रजन दस्तावेज, जिनमें पासपोर्ट और पहचान पत्र शामिल हैं, अपने पास सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध रखें। इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए वे भारतीय दूतावास से संपर्क करें। परामर्श में ईरान में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर साझा किये गये हैं जो 989128109115, 989128109109, 989128109102; 989932179359 हैं। इसके अलावा दूतावास से cons.tehran@mea.gov.in ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है।

परामर्श में कहा गया है कि ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिक, जिन्होंने अभी तक भारतीय दूतावास में पंजीकरण नहीं कराया है से अनुरोध है कि वे (https://www.meaers.com/request/home) लिंक पर पंजीकरण करें। यह लिंक दूतावास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यदि ईरान में इंटरनेट व्यवधान के कारण कोई भारतीय नागरिक स्वयं पंजीकरण करने में असमर्थ है, तो उनके परिजन भारत में यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि ईरान और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच यह तनाव कभी भी टकराव में बदल सकता है।

उत्तरकाशी पुलिस का नशे के कारोबार पर प्रहार: चरस के साथ महिला गिरफ्तार

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।

देवभूमि को नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ उत्तरकाशी पुलिस का अभियान लगातार रंग ला रहा है। बड़कोट पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक महिला तस्कर को 709 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर नशा तस्करों के नेटवर्क को करारा झटका दिया है। बरामद चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.4 लाख रुपये आंकी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय के सख्त निर्देशों के तहत चलाए जा रहे 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली।

चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ी महिला तस्कर

पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सुभाष चन्द्र के नेतृत्व में कोतवाली बड़कोट पुलिस टीम द्वारा 22 फरवरी 2026 की देर शाम यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीगाड़ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध महिला उमा देवी (56 वर्ष) को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस उस समय हैरान रह गई जब महिला के कब्जे से आटे के कट्टे में छिपाकर रखी गई 709 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब महिला से पूछताछ कर नशे के इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिससे अन्य तस्करों की गिरफ्तारी भी संभव हो सके।

उत्कृष्ट कार्य पर पुलिस टीम को मिला पुरस्कार

इस सराहनीय कार्रवाई के लिए एसएसपी कमलेश उपाध्याय ने पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए 2500 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में– उप निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह रावत, कांस्टेबल गौरव, कांस्टेबल चालक जयपाल, महिला कांस्टेबल कविता शामिल रहे।

दो माह में 6 तस्कर गिरफ्तार, 3 किलो से अधिक चरस बरामद

उत्तरकाशी पुलिस की लगातार कार्रवाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2026 के शुरुआती दो माह में ही एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 मामलों में 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान करीब 6.5 लाख रुपये कीमत की 3 किलोग्राम से अधिक चरस बरामद की गई है। एसएसपी कमलेश उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि जनपद में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी और तेज किया जाएगा तथा देवभूमि में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसुनवाई में 42 समस्याओं का मौके पर ही कराया निस्तारण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 78 शिकायतें दर्ज कराई गई। जिसमें से 42 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया शेष समस्याओं को निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।

जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि, विवाद, विद्युत, राशन, अतिक्रमण, पेयजल, पंचायतीराज, शिक्षा आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही है उन समस्याओं को त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करे।उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि जिन शिकायतों पर स्थलीय निरीक्षण

किया जाना है संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का समाधान करना सुनाश्चित करे।

उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम में दुबारा न पहुंचे,सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करले कि जो समस्या उनके माध्यम से निस्तारित की जानी थी तथा उनके द्वारा उस समस्या का निराकरण नहीं किया गया है तथा आवेदनकर्ता दुबारा अपनी समस्या को लेकर आया है, ऐसी समस्याओं को संबंधित अधिकारी दो दिन के भीतर समस्या का निराकरण करना सुनाश्चित करें, समस्या का निराकरण न होने की दशा में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।उन्होंने सभी अधिकारियों को सचेत किया है कि जन सुनवाई में क्षेत्रवासियों द्वारा जो भी समस्या दर्ज कराई जाती है उनका गंभीरता से निस्तारण करना सुनाश्चित करे।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा

हरिद्वार। बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज समस्याओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सीएम हेल्प लाइन में जो भी शिकायते दर्ज की जा रही है,उनको सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निरंकरण करना सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिए है कि 36 दिन से अधिक जो भी शिकायते लंबित है उनका निराकरण तत्परता से करना सुनिश्चित करे। जिसमें एल 1 पर 461 शिकायतें तथा एल 2 पर 95 शिकायतें निस्तारण हेतु लंबित है,जिन्हें शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए साथ ही शिकायतकर्ता से सिस्टम के माध्यम से फोन पर वार्ता करे।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह,मुख्य कोषाधिकारी अजय कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी,जिला अर्थ संख्या आधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला प्रोविजन अधिकारी अविनाश भदौरिया,जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरूंग, एआरटीओ निखिल शर्मा सहित जिला स्तरीय सम्बन्धित अधिकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादी मौजूद रहे।

एक नजर

मोबाइल रिपेयर की आड़ में चल रहा था फर्जी दस्तावेज बनाने का धंधा, एक गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सिडकुल थाना पुलिस को सत्यापन अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अभियान के दौरान मोबाईल रिपेरिंग की दुकान की आड़ में फर्जी दस्तावेज व प्रमाणपत्र बनाने के धंधे का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मौके से लैपटॉप, प्रिंटर व अन्य सामान बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक थाना सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन सत्यापन अभियान के दौरान थाना सिडकुल क्षेत्र में पिपलेश्वर मन्दिर के पास रावली महदूद में मोबाईल रिपेरिंग की दुकान में छापेमारी की तो एक व्यक्ति स्थानीय तथा बाहरी राज्यों के लोगों के फर्जी आधारा कार्ड, मार्कशीट व अन्य दस्तावेज बनाता हुआ पाया गया।

पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम पुनीत कुमार पुत्र वेदपाल सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कासमाबाद पोस्ट बुढनपुर थाना स्योहरा जिला बिजनौर उ.प्र. हाल पता पिपलेश्वर मंदिर रावली महदूद थाना सिडकुल जिला हरिद्वार बताया। आरोपित ने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मार्कशीट व अन्य इलेक्ट्रानिक दस्तावेज बनाने की जानकारी दी। आरोपी ने जारी किए गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में बताया कि जो लोग सिडकुल में नौकरी करने बाहरी राज्यों से आते हैं उनको उत्तराखण्ड के आधार कार्ड व अन्य कागजात की अवश्यकता होने पर आधार कार्ड में नाम पता चेंज व उम्र कम ज्यादा कर व प्रिंट निकालकर ग्राहकों को देता था। आरोपित की दुकान की तलाशी में 04 आधार कार्ड (02 कूटरचित), 09 हाईस्कूल अंकतालिकायें कूटरचित छायाप्रतिंया बरामद हुयी हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने दुकान से लैपटाप, लैपटाप चार्जर, स्कैनर आदि बरामद किया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया है।

सफाई कर्मचारियों का किसी भी दशा में न हो उत्पीड़न: मकवाना

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार भगवत प्रसाद मकवाना जनपद भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं सफाई कर्मचारियों के समस्याओं को लेकर नगर पालिका परिषद सभागार, लक्सर में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की समीक्षा करते हुए उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड भगवत प्रसाद मकवाना ने नगर पालिका नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि पर्यावरण मित्रों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें हर हाल में लाभ पहुंचना सुनाश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता या लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए है कि सफाई कर्मचारियों का किसी भी तरह से कोई उत्पीड़न न किया जाए। सभी कार्मिकों को समय से उनका वेतन का भुगतान किया जाए। जो कार्मिक विगत 10 वर्षों से संविदा के माध्यम से कार्य कर रहे है,उन्हें तत्काल नियमित करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि जो भी कार्मिक आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए है उन्हें संविदा एवं पीआरडी के माध्यम से रखा जाए तथा सभी को सम्मान कार्य सम्मान वेतन उपलब्ध कराया जाए।

समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि पर्यावरण मित्रो द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लोन के लिए जो आवेदन किया गया था उसमें केवल 36 लोगों को ही लोन उपलब्ध कराया गया तथा 85 आवेदन पत्र बैंक में ही लंबित पड़े है, जिस पर उन्होंने समाज कल्याण विभाग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बैंकों में लंबित आवेदन पत्रों को एक सप्ताह के भीतर बैंकों से समन्वय करते हुए आवश्यक कारवाही करते हुए पर्यावरण मित्रों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने यह भी नि दिए है कि सफाई कर्मचारियों को जो भी वर्दी एवं सफाई उपकरण दिए जाते है उन्हें नियमानुसार सभी को उपलब्ध कराए जाए तथा मृतक आश्रितों को 15 दिन के भीतर नियुक्त कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि जिन सफाई कर्मचारियों के आयुष्मान एवं गोल्डन कार्ड नहीं बनाए गए है उनके लिए शिविर आयोजित किए जाए तथा समय समय पर सभी सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परिक्षण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम सिंह,सुरेश चंद्र, ईओ नगर पालिका मोहम्मद कामिल, सुल्तानपुर नगर पंचायत ईओ प्रियंका ध्यानी सहित सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी, सफाई यूनियन के अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।

हरिद्वार में भी हुआ 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म का विरोध

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में यादव समाज के लोगों ने 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम हरिद्वार को ज्ञापन सौंपते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म के जरिए यादव समाज की छवि को धूमिल किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में हुए इस

शक्ति प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज, जाति या समुदाय के नाम पर इस प्रकार की फिल्म बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज की भावनाएं आहत होती हैं। प्रदर्शनकारियों ने शासन-प्रशासन से फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकारों और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा।

पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की अहम मुलाकात

महाकुंभ 2027 की तैयारियों, नमामि गंगे परियोजनाओं और सिंचाई–पेयजल योजनाओं को लेकर मांगी त्वरित स्वीकृति

पथ प्रवाह, नई दिल्ली

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से शिष्टाचार भेंट कर वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के सफल, सुव्यवस्थित और पर्यावरणीय दृष्टि से सतत आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग और परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि जनवरी से अप्रैल 2027 तक आयोजित होने वाले इस विशाल धार्मिक आयोजन में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। ऐसे में गंगा की निर्मलता, स्वच्छता और अविरलता बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (हस्ष्टत) के अंतर्गत ?408.82 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया, जिससे गंगा संरक्षण और आधारभूत ढांचे को समय रहते मजबूत किया जा सके।

बाढ़ सुरक्षा और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर रखा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री धामी ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए ?253 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध भी किया। इसके साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि जारी करने तथा इकबालपुर नहर प्रणाली, कनखल और जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार के प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर असिंचित क्षेत्रों के लिए 665 क्यूसेक अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा, जिससे हरिद्वार जिले के भगवानपुर और लक्सर क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से लगभग 13 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होने का अनुमान है। साथ ही क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई पेयजल समस्या के समाधान में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

केंद्र के सहयोग से दिव्य और भव्य होगा महाकुंभ

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार महाकुंभ 2027 को दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गंगा संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर तत्परता से कार्यवाही करे अधिकारी: जिलाधिकारी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिला योजना, राज्य योजना एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्गत की गई धनराशि में से अवशेष धनराशि के संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक ली।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है तथा जिन विभागों ने जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि व्यय नहीं की गई है,वह विभाग माह फरवरी के अंत तक शत प्रतिशत धनराशि व्यय करना सुनाश्चित करे,इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाए। राज्य सेक्टर के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाने है उन कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता से करते हुए स्वीकृत धनराशि का व्यय करना सुनाश्चित करे।

उन्होंने बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि जो विभाग बी एवं डी श्रेणी में है, उन्हें ए श्रेणी में आने के निर्देश दिए गए। जनपद में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिन विभागों में घोषणाएं कार्यवाही हेतु लंबित है उन घोषणाओं पर संबंधित अधिकारी तत्परता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करे, इसमें किसी भी प्रकार से कोई शिथिलता एवं विलंब न किया जाए, सभी अधिकारी गंभीरता से कार्यवाही करना सुनाश्चित करें।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि तीर्थ नगरी हरिद्वार को साफ, स्वच्छ एवं सुंदर जनपद बनाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में विगत तीन माह से निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है,जिसमें सभी अधिकारियों द्वारा अपना सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को ओर बेहतर करने के लिए चमा चम सड़क सफाई अभियान 21 फरवरी से 03 मार्च तक जनपद के शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चलाया जा रहा है, इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडल, धार्मिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ग्रामीणों को इस अभियान में शामिल करने हेतु सभी को प्रेरित करते हुए सफाई अभियान में सभी का सहयोग लिया जाए। जिससे कि जनपद हरिद्वार को साफ स्वच्छ सुंदर जनपद बनाया जा सके तथा तीर्थ नगरी में आने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं को स्वच्छ साफ वातावरण उपलब्ध हो सके तथा वह जब अपने गंतव्य को लौटे तो अपने साथ सुखद अनुभव के साथ जाए।

बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, मुख्य चिकित्साधिकारी आरके सिंह, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, मुख्य कोषाधिकारी अजय कुमार, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवि दीपक कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, प्रोजेक्ट मैनेजर पेयजल निगम (गंगा) मीनाक्षी मित्तल, मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भण्डारी सहित जिला स्तरीय सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

तुलसी चौक से बच्ची का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

नगर कोतवाली क्षेत्र में तुलसी चौक से दो साल की बच्ची का अपहरण करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्ची को अपहरण के चार घंटे बाद ही सकुशल बरामद कर लिया था, पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। आरोपी नशे का आदी है और बच्ची से भीख मंगवाने के लिए उसने अपहरण किया था।

बतादें बीती 19 फरवरी को तुलसी चौक से दो साल की मासूम का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया था। जिसके संबंध में सोनी पत्नी स्व. इंद्रपाल, मूल निवासी ग्राम कसुआ बड़सरा अतरौली, जनपद हरदोई (उप्र), हाल निवासी गणेश घाट मायापुर, कोतवाली नगर, हरिद्वार ने चौकी मायापुर पर बच्ची के लापता हो जाने के संबंध में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गयी। करीब चार घंटे बाद पुलिस ने बच्ची को देवपुरा क्षेत्र में ऋषिकुल तिराहे के पास लावारिस अवस्था में सकुशल बरामद कर लिया।

घटना के अनावरण के लिए गठित टीमों द्वारा 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग के अपहरणकर्ता के रूप में रवि

कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी निकट राधाकृष्ण आश्रम, सोनी ज्वैलर्स के पास, कोतवाली ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार, उम्र 28 वर्ष के रूप में पहचान हुई। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने देर रात्रि श्रीराम घाट के सामने पार्क के पास, नहर पटरी मायापुर क्षेत्र से आरोपी रवि कुमार को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह नशे का आदी है। उसने 19 फरवरी की रात्रि को तुलसी चौक से बालिका को उठाया और देवपुरा होते हुए एक घाट पर ले जाकर रुक गया। अगले दिन वह बालिका को अन्य शहर ले जाकर उससे भीख मंगवाकर नशे के लिए धन अर्जित करने की योजना बना रहा था। ऋषिकुल तिराहे बस अड्डे पर पुलिस की सघन चेकिंग देखकर घबराकर वह बालिका को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया है।

अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्यवाही, वर्षों से जमे अतिक्रमण को मिनटों में हटाया

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने रेलवे स्टेशन और रोडवेज के पास सड़क पर फुटपाथ सजा कर किये गए अतिक्रमण को सख्ती से हटा दिया। इस दौरान करीब 80 अवैध दुकानों को हटाकर उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि फिर से कब्जा करने का प्रयास किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कुछ दुकानदारों का सामान भी कब्जे में लिया गया। जनपद में किसी भी क्षेत्र ने कोई अतिक्रमण न हो इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस को अपने अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध आवश्यकनगर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में देवपुरा चौक से लेकर रेलवे स्टेशन हरिद्वार तक बाई ओर फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को हटाते हुए फुटपाथ को खाली कराया गया, जिसमें अन्य अतिक्रमण के साथ-साथ बस स्टैण्ड के सामने रेलवे स्टेशन की दीवार से लगती हुई लगभग 80 अस्थाई दुकाने तथा रेहडी ठेली हटायी गयी। उन्होंने अवगत कराया है कि शहर के अन्तर्गत जिन फुटपाथों पर अतिक्रमण है, उनको तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराते हुए फुटपाथ खाली कराया जायेगा। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा नगर हरिद्वार के समस्त व्यापारियों एवं आम जनमानस

से अपील की गई कि जिन-जिन व्यापारियों एवं जनमानस द्वारा अपनी दुकान का सामान, रेहड़ी, ठेली फुटपाथ पर लगाई गयी है, वह उनकों स्वयं तत्काल हटाकर फुटपाथ को खाली कर दें। अन्यथा नगर निगम हरिद्वार की टीम द्वारा उनका सामान जब्त कर लिया जायेगा। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा यह भी बताया गया कि जहाँ-जहाँ आज फुटपाथ खाली कराया गया है, उसकी आज ही साफ-सफाई किये जाने हेतु नगर निगम हरिद्वार की टीम को निर्देशित किया गया है तथा क्षतिग्रस्त फुटपाथ की मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कई व्यक्तियों द्वारा सडको तथा नो पार्किंग जोन में गाड़िया खड़ी की गयी है, जिससें आम जनमानस के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा जाम लगने की सम्भावना बनी रहती है, उन्होंने मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़को/नो पार्किंग जोन में पार्क किये गये वाहनों के विरूद्ध युद्धस्तर अभियान चलाते हुए पुलिस एक्ट में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने फुटपाथ से लगती हुई रेलवे की भूमि पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा झोपड़ी डाली गयी है. इस सम्बन्ध में रेलवे के अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर निर्देशित किया गया कि वें अपनी भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटवा दें। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा नगर निगम एवं पुलिस को निर्देशित किया गया कि जिन-जिन स्थलों से अतिक्रमण हटवा कर खाली किया जा रहा है, वहाँ पुनः अतिक्रमण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ भारी जुर्माना लगाये जाने की कार्यवाही भी की जाए।

संपादकीय

धामी सरकार का आखिरी बजट: चुनावी से पहले सरकार की नीयत और नीति की असली परीक्षा

उत्तराखंड में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले प्रस्तुत होने वाला यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राथमिकताओं और जनविश्वास की निर्णायक परीक्षा है। यह इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इसकी हर घोषणा, हर प्रावधान और हर वादा सीधे जनता की कसौटी पर परखा जाएगा।

चुनावी वर्ष से पहले पेश होने वाले बजट से स्वाभाविक रूप से जनता को राहत, नई योजनाओं और विकास की गति तेज होने की उम्मीद रहती है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह लोकलुभावन घोषणाओं और वास्तविक विकास के बीच संतुलन बनाए। यदि बजट केवल चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, तो उसका प्रभाव अल्पकालिक होगा, लेकिन यदि इसमें दीर्घकालिक विकास की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है, तो यह राज्य के भविष्य को मजबूत आधार दे सकता है।

उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याओं में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव शामिल है। युवा रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर जा रहे हैं, जबकि गांव खाली हो रहे हैं। ऐसे में इस बजट से अपेक्षा है कि स्वरोजगार, स्थानीय उद्योग, पर्यटन आधारित रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रावधान किए जाएं। केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की स्पष्ट कार्ययोजना भी सामने आनी चाहिए।

साथ ही, राज्य में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण, यातायात दबाव और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए संतुलित निवेश जरूरी है। उत्तराखंड एक आपदा-संवेदनशील राज्य है, इसलिए विकास की योजनाएं पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर ही बनाई जानी चाहिए।

यह बजट सरकार के पिछले पांच वर्षों के कामकाज का प्रतिबिंब भी होगा। जनता यह देखना चाहती है कि जिन वादों के साथ सरकार सत्ता में आई थी, वे कितने पूरे हुए और भविष्य के लिए उसकी क्या स्पष्ट दृष्टि है। विपक्ष के लिए भी यह बजट सरकार को जवाबदेह बनाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

चुनावी वर्ष से पहले का यह बजट सरकार के लिए विश्वास अर्जित करने का आखिरी बड़ा मौका है। अब जनता केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस परिणाम चाहती है। यह बजट तय करेगा कि सरकार विकास की गंभीर और दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ रही है या यह केवल चुनावी वर्ष की औपचारिकता बनकर रह जाएगा। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, उम्मीदों और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक अध्याय साबित होगा।

न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर उठते सवाल?

सनत जैन

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की खंडपीठ में सोमवार को एक असहज स्थिति देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, अडानी और अंबानी के लिए तुरंत बेंच बना दी जाती है। लेकिन एनजेएसी की महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उनका इतना कहते ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन्हें जमकर कोर्ट के अंदर फटकार लगाई। उन्हें मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप जो भी मेरी कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उसे लेकर भविष्य में सावधान रहें। आपने मुझे चंडीगढ़ और दिल्ली में देखा है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप जिस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, वैसा आगे भी करते रहेंगे। कुछ इसी तरह की स्थिति शुक्रवार को भी बनी, जब एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुस्से में आ गए थे। उन्होंने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले वह वकीलों की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीकी की मदद से जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही हैं। उस पर उन्होंने नाराजी व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका देखकर उन्होंने कहा ऐसा लगता है, भगवान जनहित याचिका के कानून से बचाए। कुछ इसी तरह की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में तब देखने को मिली जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा सरमा की हेट स्पीच की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। मुख्य न्यायाधीश ने उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं को असम हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठतम वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई करने या असम के अलावा अन्य किसी हाईकोर्ट में तुरंत सुनवाई करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश ने असहमति व्यक्त करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। जबकि कई राज्यों की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पिछले कुछ महीनो में उसमें आदेश जारी किए हैं। जिन राज्यों की याचिका स्वीकार की गई हैं, उनमें अमूमन डबल इंजन की सरकारें हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर बार-बार सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जिस तरह से वरिष्ठ वकीलों और सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली और सरकारी दबाव पर मामले की सुनवाई को लेकर असहमति बढ़ती चली जा रही है, इससे न्याय पालिका की एक ऐसी छवि विकसित हो रही है। सरकार या सरकार से जुड़े हुए मामलों में सुप्रीम कोर्ट त्वरित सुनवाई करने से बचती है। यदि याचिका स्वीकार हो भी जाती है। नोटिस जारी हो जाते हैं। उसके बाद तारीख पर तारीख का जो नया खेल शुरू होता है, उससे निश्चित रूप से सरकार को मदद होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित याचिका, एसआईआर का मामला इन दिनों चर्चाओं में है। बिहार चुनाव के कई माह पहले से याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जिसका फैसला अभी तक नहीं आया है। इसी बीच बिहार विधानसभा के चुनाव हो गए। सुप्रीम कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही है, सुनवाई भी हो रही है, कोई फैसला अभी तक नहीं आया। अगले कुछ ही महीना में पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव होने हैं। जिसके कारण न्यायपालिका की कार्य प्रणाली को चुनाव आयोग या सरकार को फायदा पहुंचाने के रूप में देखा जाने लगा है। करोडों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर जो निर्देश चुनाव आयोग को दिए गए, उनका पालन चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती दे दी। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की मनमानी पर कोई रोक नहीं लगाई। पिछले कुछ वर्षों में कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित हैं। उन पर अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। उसके कारण न्याय पालिका की छवि को लेकर आम आदमी में वह विश्वास नहीं रहा, जो न्यायपालिका के प्रति होना चाहिए। न्याय पालिका सरकार के खिलाफ कोई भी आदेश और निर्देश देने से बचती है। ऐसे मामलों से बचने के लिए या तो याचिका स्वीकार नहीं की जा रही हैं, यदि स्वीकार कर ली जाती है, तो उसकी समय पर सुनवाई और फैसला नहीं हो रहे हैं।

भारत की खुशहाली और आर्थिक मजबूती का आधार: केंद्रीय उत्पाद शुल्क

दिलीप कुमार पाठक

भारत की आर्थिक प्रगति के पीछे उन हजारों हाथों का योगदान है, जो देश के राजस्व को मजबूत करने के लिए दिन-रात काम करते हैं। इन्हीं प्रयासों को सम्मान देने और आम जनता को कर व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 24 फरवरी को देश में एक विशेष अवसर के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। यह समय हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसी दिन साल 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाया गया था। भले ही आज के दौर में टैक्स की प्रणालियां बदल गई हों और जीएसटी ने एक बड़ा स्थान ले लिया हो, लेकिन देश की तरक्की में उत्पाद शुल्क का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। एक आम नागरिक के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर टैक्स चुकाने से उसे क्या मिलता है। इसका जवाब बहुत ही सरल और सुंदर है। जब देश की फैक्ट्रियों में सामान बनता है और उस पर सरकार को शुल्क मिलता है, तो वही पैसा घूमकर समाज के कल्याण के लिए वापस आता है। हमारे गाँव और शहरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें, अंधेरे को दूर करती बिजली की रोशनी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के आधुनिक हथियार, यह सब उसी कर के पैसे से संभव हो पाता है जो एक जिम्मेदार उद्यमी और नागरिक द्वारा चुकाया जाता है। इस प्रकार, कर का भुगतान करना केवल एक कानूनी काम नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर राष्ट्र की सेवा करने जैसा है।

इसी संदर्भ में यह समझना भी जरूरी है कि एक मजबूत कर प्रणाली ही देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी खतरों से निपटने की शक्ति प्रदान करती है। जब सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, तभी नई तकनीकों और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश किया जा सकता है। यह राजस्व ही है जो आपदाओं के समय राहत कार्य चलाने और देश के करोड़ों गरीब परिवारों तक मुफ्त राशन और जरूरी सुविधाएं पहुँचाने में मदद करता है। बिना मजबूत वित्तीय आधार के कोई भी देश अपने नागरिकों के सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए, उत्पाद शुल्क केवल एक सरकारी उगाही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक सशक्त माध्यम भी है, जो उद्योगों से कर लेकर समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान में खर्च किया जाता है। समय के साथ सरकारी कामकाज के तरीकों में भी बड़ा बदलाव आया है। आज का दौर डिजिटल क्रांति का है और अब टैक्स चुकाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं रह गई है। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को इतना सरल और पारदर्शी बना दिया है कि कोई भी व्यापारी घर बैठे अपना हिसाब-किताब पूरा कर सकता है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बल्कि व्यापार करने में भी आसानी हुई है। यह समय उन अधिकारियों और कर्मचारियों के परिश्रम को भी सलाम करने का है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि देश का खजाना सुरक्षित रहे और कहीं भी राजस्व की चोरी न हो। इसके साथ ही, हमें यह भी समझना होगा कि कर के माध्यम से एकत्र किया गया धन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ईंधन की तरह काम करता है। जब हमारे उद्योग जगत में पारदर्शिता बढ़ती है, तो विदेशी निवेश भी भारत की ओर आकर्षित होता है। यह निवेश न केवल नई फैक्ट्रियां लगाता है, बल्कि देश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। हमारी आर्थिक नीतियां तभी सफल हो सकती हैं जब राजस्व विभाग और करदाता के बीच विश्वास का एक मजबूत रिश्ता हो। यही विश्वास आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर और भी ऊंचा स्थान दिलाएगा।

किसी भी महान राष्ट्र का निर्माण केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि वहां के नागरिकों की ईमानदारी से होता है। जब हम ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं, तो हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हैं। यह अवसर हमें यही सीख देता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। कर की चोरी न केवल अपराध है, बल्कि यह देश के विकास की गति को रोकने जैसा है। एक पारदर्शी और मजबूत कर व्यवस्था ही एक स्वस्थ समाज और शक्तिशाली भारत की पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब ऐसी संस्थाओं और व्यवस्थाओं की भूमिका और भी बढ़ जाती है। विकसित भारत का सपना तभी सच होगा जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझेगा। आइए, आज हम यह संकल्प लें कि हम कर चोरी जैसी बुराइयों को खत्म करने में सहयोग करेंगे और एक ईमानदार करदाता बनकर देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे। हमारी छोटी सी ईमानदारी ही कल के समृद्ध भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

एआई तकनीक में विश्व का नेतृत्व करेगा भारत

मनोज कुमार अग्रवाल

राजधानी नई दिल्ली के में आयोजित पांच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का शनिवार को समापन हो गया, लेकिन इस सम्मेलन की सफलता ने भारत को ग्लोबल साउथ में अग्रणी नेतृत्वकारी देश के रूप में स्थापित कर दिया है। इस शिखर सम्मेलन में 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया जाना न केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि है, बल्कि यह भारत की उस सोच की वैश्विक स्वीकृति भी है, जो तकनीक को मानव कल्याण से जोड़कर देखती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मानव-केंद्रित एआई दृष्टिकोण औउखर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को जिस व्यापक वैश्विक समर्थन मिला है, वह बताता है कि दुनिया तकनीकी प्रगति को केवल आर्थिक लाभ लाभ के नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के संदर्भ में भी देखना चाहती है।21 फ़रवरी को 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट डिक्लेरेशन का समर्थन किया। इनमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इस डिक्लेरेशन में किए गए सारे कमिटमेंट स्वैच्छिक हैं, यानी ये उन देशों की इच्छा पर निर्भर है कि वे इसके मुताबिक़ कितना काम करते हैं। इस डिक्लेरेशन में देशों ने इस समिट में सात चक्र में हुई चर्चाओं का संज्ञान लिया और कहा कि वे स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में हुए एआई समिट से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के विकास में अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान भी किया जाएगा। आपको पता हो कि 88 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। यह सिद्धांत केवल एक सांस्कृतिक वाक्यांश नहीं, बल्कि तकनीकी विकास के लिए एक नैतिक दिशा है। ऐसे समय में जब एआई को लेकर विश्व में प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण और प्रभुत्व की राजनीति हावी है, भारत ने समावेशी और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर एक संतुलित विकल्प दिया है। समिट के दौरान एआई क्षेत्र में 250 अरब डॉलर के संभावित निवेश का भरोसा जताया जाना भारत की आर्थिक क्षमता और नीति स्थिरता पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। यह निवेश केवल पूंजी का प्रवाह नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार का अवसर है। साथ ही यह फंडिंग दर्शाती है कि दुनिया भारत को एआई के भविष्य के केंद्र के रूप में देख रही है। भारत पहले से ही आईटी और डिजिटल सेवाओं में वैश्विक केंद्र रहा है। अब एआई में नेतृत्व का अर्थ है कि उच्च कौशल वाले रोजगार, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा और वैश्विक कंपनियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का प्रमुख केंद्र बनना। यदि यह निवेश सही दिशा में लागू हुआ, तो भारत न केवल उपभोक्ता बल्कि एआई समाधानों का प्रमुख उत्पादक भी बन सकता है। एआई की तीन प्रगति ने कई नैतिक और सुरक्षा संबंधी प्रश्न भी खड़े किए हैं, जिसमें डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदमिक पक्षपात, साइबर सुरक्षा और रोजगार पर प्रभाव जैसी चिंताएं गंभीर हैं। भारत एआई इम्पैक्ट समिट का एक प्रमुख उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान खोजना था। भारत ने जिस प्रकार विकासशील देशों की आवाज को मंच दिया, वह अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह तथ्य कि पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित हुआ, अपने आप में ऐतिहासिक है। लंबे समय तक तकनीकी विमर्श विकसित देशों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है। भारत ने इस परंपरा को बदलते हुए यह दर्शाया कि नवाचार और नीति-निर्माण में विकासशील देशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ग्लोबल साउथ के कई देश डिजिटल अवसंरचना के विस्तार और डेटा आधारित शासन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर आदि पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा चुका है। अब एआई के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का साझा मॉडल विकसित किया जा सकता है, जिससे छोटे और मध्यम आय वाले देशों को लाभ हो। भारत की युवा आबादी और तकनीकी प्रतिभा उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। विश्व की अग्रणी टेक कंपनियों में भारतीय मूल के विशेषज्ञों की मजबूत उपस्थिति यह दर्शाती है कि देश में गणित और इंजीनियरिंग की ठोस परंपरा है। चुनौती यह है कि यह प्रतिभा देश के भीतर शोध और उत्पाद विकास में रूपांतरित हो। जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स में बढ़ती फंडिंग एक सकारात्मक संकेत है। निवेशकों का बढ़ता भरोसा बताता है कि भारतीय उद्यमी केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि उत्पाद-निर्माता बनने की ओर अग्रसर हैं। हालांकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचने के लिए दीर्घकालिक और धैर्यपूर्ण निवेश आवश्यक होगा। अनुसंधान-आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, उद्योग और सरकार के बीच मजबूत सहयोग की जरूरत है। एआई अब प्रयोगशाला की अवधारणा नहीं, बल्कि व्यावसायिक वास्तविकता बन चुका है। वित्त, बीमा, दूरसंचार, ई-कॉमर्स और विनिर्माण क्षेत्रों में एआई आधारित विश्लेषण और स्वचालन से उत्पादकता में वृद्धि देखी जा रही है। यदि यह प्रवृत्ति स्थायी बनती है, तो एआई भारत की आर्थिक वृद्धि दर में प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है। विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में एआई के प्रयोग से सामाजिक प्रभाव की व्यापक संभावनाए हैं। कृषि में सटीक खेती, स्वास्थ्य में रोग-पूर्वानुमान, शिक्षा में अनुकूलित शिक्षण और पर्यावरण में जलवायु विश्लेषण ये सभी क्षेत्र भारत के विकास एजेंडा से सीधे जुड़े हैं। यदि एआई समाधान ग्रामीण भारत तक पहुंचते हैं, तो समावेशी विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति संभव है। भारत की बहुभाषी सांस्कृतिक संरचना एआई के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। यदि भारत भारतीय भाषाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट और बहुभाषी मॉडल विकसित करता है, तो वह न केवल घरेलू बाजार को सशक्त करेगा, बल्कि वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए समाधान भी निर्यात कर सकेगा। मीडिया और रचनात्मक उद्योगों में एआई आधारित सामग्री निर्माण, अनुवाद और वॉयस इंटरफेस से नए आर्थिक अवसर उत्पन हो सकते हैं। एआई अवसंरचना के विस्तार के साथ ऊर्जा और जल-उपयोग जैसे प्रश्न भी जुड़े हैं। डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या पर्यावरणीय दबाव उत्पन कर सकती है। अतः एआई विकास को अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता नीतियों के साथ संतुलित करना आवश्यक संतुलित कर है। तकनीकी नेतृत्व तभी टिकाऊ होगा जब वह पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। साथ ही, एआई के कारण पारंपरिक नौकरियों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कौशल उन्नयन को नई पीढ़ी को उभरती तकनीकों के अनुरूप तैयार करना अनिवार्य है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत केवल डिजिटल उपभोक्ता रष्ट नहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी विमर्श का नेतृत्व करने में सक्षम है।

कुंभ के लिए केंद्र से 500 करोड़ की सौगात, मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखंड में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा सहयोग प्रदान किया है। भारत सरकार द्वारा कुंभ मेला आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण सहयोग बताते हुए कहा कि इससे कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर

धामी ने कहा कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक समरसता का विश्वविख्यात महापर्व है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत यह धनराशि कुंभ क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ यातायात प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे संबंधित विकास कार्यों को गति मिलेगी और आयोजन को उच्च स्तर पर संपन्न कराने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री से कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन के लिए वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए यह राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है।

पुष्कर धामी ने कहा कि चारधाम परियोजना, ऑल वेदर रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों में केंद्र सरकार का सहयोग उत्तराखंड के लिए संबल साबित हुआ है। अब कुंभ मेला 2027 के लिए मिली यह वित्तीय सहायता राज्य सरकार के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से कुंभ मेला 2027 ऐतिहासिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोरोनेशन हॉस्पिटल का डीएम सविन बंसल ने किया औचक निरीक्षण

पैथोलॉजी का समय बढ़ा, ब्लड बैंक कार्य में तेजी के निर्देश, चंदन लैब की 3 माह की रिपोर्ट तलब

पथ प्रवाह, देहरादून

जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और जिला चिकित्सालय कोरोनेशन की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, निर्माणाधीन ब्लड बैंक, केंद्रीय पैथोलॉजी, चंदन लैब, किचन, गायनी ओटी, ओपीडी, वेयरहाउस, इमरजेंसी वार्ड और पार्किंग व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय मौके पर ही लिए।

पैथोलॉजी का समय बढ़ाकर मरीजों को दी राहत

निरीक्षण के दौरान केंद्रीय पैथोलॉजी के बाहर मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतार देखकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल संज्ञान लिया। जानकारी मिली कि लैब का समय सुबह 11 बजे तक ही सीमित होने के कारण भीड़ बढ़ रही है। इस पर डीएम ने जनसुविधा को प्राथमिकता देते हुए पैथोलॉजी का समय तत्काल प्रभाव से एक घंटे बढ़ाकर अब दोपहर 12 बजे तक करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रतीक्षा कर रहे सभी मरीजों के सैंपल उसी दिन लिए जाएं।

चंदन लैब का आधा भुगतान रोकने के निर्देश

अस्पताल में अनुबंधित चंदन लैब का

निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल

ने 24 घंटे सेवाएं संचालित होने के दावे की जांच की। रात्रि में लिए गए सैंपलों का विवरण मांगे जाने पर लैब प्रभारी संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सकीं। इस पर डीएम ने उप जिलाधिकारी सदर और मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि पिछले तीन माह के दिन और रात के सैंपलों की विस्तृत जांच कर संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही अनुबंध की शर्तों का पालन न पाए जाने की स्थिति में लैब का आधा भुगतान रोकने के निर्देश भी दिए गए।

निर्माणाधीन ब्लड बैंक का कार्य 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश

निर्माणाधीन ब्लड बैंक का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को 15 मार्च 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लड बैंक के कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के साथ ही चिकित्सक, स्टाफ और उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही शुरू कर दी गई हैं।

ओपीडी मरम्मत के लिए 10 लाख स्वीकृत

अस्पताल की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी ने किचन, गायनी ऑपरेशन थिएटर, वेयरहाउस और ओपीडी की मरम्मत हेतु 10 लाख रुपये की धनराशि मौके पर ही स्वीकृत की। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र कार्य प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गायनी चिकित्सक की कमी पर संयुक्त रिपोर्ट तलब

निरीक्षण के दौरान यह शिकायत भी सामने आई कि गायनी चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। इस गंभीर विषय पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर और मुख्य चिकित्साधिकारी को संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

बाल वार्ड में बच्चों के लिए सुविधा

बाल चिकित्सा वार्ड के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखने और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाईब्रेरी के साथ ड्राइंग और कलर की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देने के बजाय उन्हें रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें।

हिलांस कैंटीन और ऑटोमेटेड पार्किंग व्यवस्था की सराहना

अस्पताल परिसर में संचालित एसएचजीएस हिलांस कैंटीन का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। प्रतिदिन लगभग 500 लोगों की क्षमता से संचालित कैंटीन से मरीजों और तीमारदारों ने संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग व्यवस्था भी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित पाई गई, जिससे मरीजों और आमजन को काफी राहत मिल रही है।

जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता

जिलाधिकारी सविन बंसल ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और दवा आपूर्ति से संबंधित कंपनियों के साथ हुए अनुबंधों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अक्षम्य बताते हुए नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

अस्पताल की सूरत बदलने का प्रयास

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कोरोनेशन अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक मन्नू जैन, समाजसेवी मनमोहन खत्री सहित अन्य चिकित्सक और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की कड़ी कार्रवाई, 13 नमूने जांच को भेजे

पथ प्रवाह, पौड़ी। होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद में मिलावटखोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। सोमवार को पौड़ी नगर में दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मिठाई, सरसों तेल और जूस सहित 13 नमूने लेकर राजकीय खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे गए। निरीक्षण के दौरान मिठाई विक्रेताओं को स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) पी.सी. जोशी ने बताया कि प्रातः बाहरी क्षेत्रों से आने वाले दूध एवं दुग्ध पदार्थों के वाहनों की जांच की गई। इस दौरान आनंदा और मदर डेयरी के दूध व पनीर के नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु भेजे गए। साथ ही नगर की विभिन्न मिठाई दुकानों का निरीक्षण कर मिठाइयों के नमूने भी जांच के लिए भेजे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत यदि कोई नमूना मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि गत माह खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल द्वारा 'जय श्री' ब्रांड सरसों तेल का नमूना निगरानी जांच हेतु भेजा

गया था, जो मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। इस प्रकरण में भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वर्तमान में 41 वाद विचाराधीन हैं, जिनमें से तीन मामलों में न्यायालय द्वारा संबंधित खाद्य कारोबारियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। सैंपलिंग अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप मिश्रा सहित विभागीय टीम उपस्थित रही।

बिजली बिल और सरचार्ज के विरोध में विधायक अनुपमा रावत की पदयात्रा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बिजली विभाग की कथित मनमानी, बढ़े हुए बिल और सरचार्ज के विरोध में अनुपमा रावत ने 28 फरवरी को पदयात्रा निकालने की घोषणा की है। यह पदयात्रा ग्राम नूरपुर पंजनहेड़ी से शुरू होकर सिंहद्वार तक निकाली जाएगी। पदयात्रा को लेकर कृष्णानगर स्थित पूर्व मेयर अनीता शर्मा के कैंप कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक अनुपमा रावत ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा लगातार बिजली और पानी के बिलों में बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग जनता का शोषण कर रहा है और सरकार इस मुद्दे पर संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने कहा, 'जनता को भेजे जा रहे बिलों में भारी सरचार्ज जोड़ा जा रहा है, जिससे आम परिवारों का बजट बिगड़ रहा है। लोगों की शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए 28 फरवरी को पदयात्रा निकाली जाएगी, ताकि सरकार और अधिकारियों को जगाया जा सके। विधायक अनुपमा रावत ने यह भी मांग की कि बिजली बिलों पर लगाए गए सरचार्ज में राहत दी जाए और आम जनता को राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया

तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बैठक में मौजूद पूर्व सभासद अशोक शर्मा ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता परेशान है और अधिकारियों द्वारा आम लोगों की शिकायतों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब लोग अपनी समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। ऐसे में सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए जन आंदोलन जरूरी हो गया है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से पदयात्रा में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते टैक्स और सरचार्ज से जनता त्रस्त हो चुकी है और अब जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी। बैठक में महेश प्रताप राणा, अरविंद शर्मा, राजबीर सिंह चौहान, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैश खुराना, जगत सिंह रावत, लव गुप्ता, अंजू मिश्रा, अंजू द्विवेदी, बीएस तेजियान, वसीम सलमानी, कैलाश भट्ट, दिनेश वालिया, जतिन हांडा, आशु श्रीवास्तव, रामबाबू बंसल, सुंदर सिंह मनवाल, बृजमोहन बड़थ्वाल, दिनेश पुंडीर, दीपक कोरी, पार्षद सुनील कुमार, हिमांशु गुप्ता, सुमित त्यागी, विवेक भूषण विक्की, उज्ज्वल वालिया, मोनिक धवन, शाहनवाज कुरैशी, विक्रम शाह, मेहरबान खान, पुनीत कुमार, अनिल भास्कर, राजेंद्र श्रीवास्तव, रणवीर शर्मा, रकित वालिया, शुभम अग्रवाल और आशु भारद्वाज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

डीएम स्वाति एस भदौरिया ने सुनी फरियादियों की आवाज, मौके पर कराया समस्याओं का समाधान

पथ प्रवाह, पौड़ी।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में एक दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष नितिगत प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

नई शिकायतों के साथ-साथ पूर्व में दर्ज प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की गई। यमकेश्वर के मोगपुर गांव निवासी रुपेश दत्त शर्मा की भूमि पैमाइश संबंधी शिकायत पर उपजिलाधिकारी यमकेश्वर को निर्देशित किया गया कि अगले ही दिन राजस्व टीम भेजकर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में

पैमाइश कर आख्या प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में पारदर्शिता अनिवार्य है, ताकि ग्रामीणों को न्यायोचित अधिकार समय पर मिल सके और उन्हें अनावश्यक कार्यालयी चक्कर न लगाने पड़ें।

जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल स्रोतों की स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि यह सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। जिलाधिकारी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं में बाधा जनजीवन को प्रभावित करती है, इसलिए ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। इसके अलावा पेयजल, शिक्षा, वन व राजस्व, स्वास्थ्य व उरेडा विभाग सम्बन्धी पूर्व शिकायतों पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिये।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

जनता मिलन कार्यक्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिवमोहन शुक्ला, जिला पंचायतराज अधिकारी जितेन्द्र कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र कुमार, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भण्डारी, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबरिया, जिला परीवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग अभिनव रावत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

बहुउद्देश्यीय शिविर में 33 शिकायतें दर्ज, 7 का मौके पर निस्तारण

पथ प्रवाह, पौड़ी। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को विकासखंड बीरोंखाल की न्याय पंचायत दुनाव के अंतर्गत पंचायत भवन तैली पखोली में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी बीरोंखाल कृष्णा त्रिपाठी ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने 33 शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें से 07 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से 226 लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया जबकि 01 ग्रामीणों का प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु आवेदन पत्र भरवाया गया। उपजिलाधिकारी ने कहा कि शिविरों के माध्यम से विभाग जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तथा विभागीय स्टॉलों के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सहकारिता, पंचायतीराज, कृषि, उद्यान, खाद्य पूर्ति और राजस्व सहित 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से 226 लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी/अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग बैजरो लोकेश सारस्वत, खंड विकास अधिकारी सुदर्शन सिंह बुटोला सहित अन्य जन प्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पांच कुंतल पनीर किया गया जब्त, सैंपल जांच के लिए भेजे

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार महिमानंद जोशी ने बताया कि आगामी होली के पर्व एवं रमजान को ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री में किसी तरह का कोई मिलावट न हो इसके दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में निरीक्षण और छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में उपायुक्त खाद्य सुरक्षा गढ़वाल आरएस रावत के नेतृत्व एवं उनके व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन व कैलाश चन्द्र टम्टा के साथ इक्कडू चौक, सराय स्थित पनीर सप्लायर यूनिट चौहान डेयरी का निरीक्षण किया गया। मौके पर डीप फ्रीजर में लगभग 05 क्विंटल पनीर संग्रहित मिला, जिसमें से पनीर के 02 नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु लिये गये। मौके पर प्रस्तुत फ़ूड लाइसेंस नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र का मिला जबकि उक्त पनीर खाद्य प्रतिष्ठान तहसील हरिद्वार में स्थित है। इसके अलावा मौके पर उक्त पनीर का क्रय व विक्रय इनवॉइस रिकार्ड भी नहीं मिला, पूछताछ में उक्त डेयरी के मालिक रहीस अहमद ने बताया कि उसने उक्त पनीर मथुरा की सोनू डेयरी से मंगवाया है तथा हरिद्वार शहर में सप्लाई करता है। मौके पर मिली उक्त अनियमितताओं के कारण पनीर मालिक को नोटिस जारी किया गया तथा 03 दिन के अन्दर तहसील हरिद्वार में फ़ूड लाइसेंस बनवाने, पनीर का क्रय इनवॉइस प्रस्तुत करने तथा तापमान नियंत्रित प्रणाली में ही पनीर का संग्रह व विक्रय करने के आदेश दिये गये, यदि उक्त पनीर मालिक संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करता है तो 03 दिन के बाद पनीर के संग्रह व विक्रय पर रोक लगा दी जायेगी तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मेलाधिकारी ने किया कुंभ मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिये दिशा निर्देश

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को व्यवस्थित एवं समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मेलाधिकारी सोनिका ने सोमवार को कुंभ नगरी के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मेलाधिकारी ने भीड़ प्रबंधन, पार्किंग एवं ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित प्रस्तावित योजनाओं की मौके पर समीक्षा करते हुए कहा कि कुंभ जैसे विराट आयोजन के लिए सुविचारित योजना, समन्वित कार्यप्रणाली तथा निरंतर निगरानी आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर व्यवस्थाओं की व्यवहारिकता, संभावित चुनौतियों तथा उनके समाधान पर चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान मेला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैरागी कैंप, दक्ष क्षेत्र, जगजीतपुर, गौरीशंकर क्षेत्र तथा नजीबाबाद मार्ग स्थित कुंभ नगरी के प्रवेश स्थल प्वाइंट 4.2 का भ्रमण किया गया। मेलाधिकारी ने इन क्षेत्रों में पार्किंग स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ सभी सेक्टरों में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी

जोर दिया।

शौचालयों की रखी जाए पर्याप्त संख्या

उन्होंने निर्देशित किया कि पेयजल आपूर्ति की निरंतर व्यवस्था, पर्याप्त संख्या में शौचालयों की स्थापना, नियमित साफ-सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, समुचित प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। प्रत्येक सेक्टर में चिकित्सा सहायता केंद्र एवं आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

पार्किंग स्थल का समय से कराए समतलीकरण

मेलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी चिन्हित अस्थायी पार्किंग स्थलों का समय से समतलीकरण कराया जाए, जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा संपर्क मार्गों को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालु नगर के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश किए बिना ही सुगमतापूर्वक एवं सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित स्नानघाटों तक पहुंच सकें। इसके लिए प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

निर्माण कार्यों को ध्यान में रखकर तैयार करें कार्ययोजना

मेलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड तथा नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजना को ध्यान में रखते हुए पार्किंग एवं ट्रैफिक प्रबंधन की कार्ययोजना में आवश्यक संशोधन किये जांय। इस दौरान एसपी (सिटी) अभय सिंह ने भीड़ प्रबंधन एवं यातायात नियंत्रण की प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी दी। उप मेलाधिकारी मनजीत सिंह ने संबंधित क्षेत्रों में की जाने वाली व्यवस्थाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।

मार्च माह तक सभी लक्ष्यों को पूरा करें सभी अधिकारी: सीडीओ

पथ प्रवाह, पौड़ी।

विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में विकास विभाग की मासिक स्टाफ बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की हुई। बैठक में रोजगार सृजन, स्वरोजगार, विभागीय समन्वय और लंबित कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सारा योजना के स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति लाने को कहा। उन्होंने मनरेगा और अन्य विभागों के कन्वर्जेंस के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगारपरक कार्य तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल ऋण स्वीकृत एवं वितरित कर उनके व्यवसाय शुरू कराने, रेशम एवं डेरी योजनाओं में विभागीय तालमेल बढ़ाने तथा कृषि, उद्यान और पशुपालन विभागों के साथ ब्लॉक स्तर पर

समन्वय बैठक कर ठोस कार्ययोजना लागू करने को कहा।

स्पष्ट किया कि मनरेगा में 60 दिन से अधिक रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों को 'प्रोजेक्ट उन्नति' के तहत आरसेटी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर मिल सकें। रीप योजना के अंतर्गत ऐमेनिटी सेंटर, कलेक्शन सेंटर एवं समुदाय आधारित कार्ययोजनाओं को प्राथमिकता से शुरू करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मेरी गांव मेरी सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर और पलायन रोकथाम से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्च माह तक कार्यों में स्पष्ट प्रगति लाएं। उन्होंने जॉब कार्डों की स्थिति और लाभार्थियों के सत्यापन की भी जानकारी ली।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, परियोजना प्रबंधक रीप कुलदीप बिष्ट, खंड विकास अधिकारी कल्जीखाल चंद्र प्रकाश बलूनी, पाबौ हरेंद्र कोली, सहायक खंड विकास अधिकारी पौड़ी दिनेश नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नीलकंठ महादेव में आधुनिक पार्किंग और 2 बेड का आकस्मिक स्वास्थ्य केंद्र

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल नीलकंठ महादेव मंदिर में बहुप्रतीक्षित बहुमंजिला पार्किंग निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। आज राज्य सचिवालय में आवास सचिव डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में नीलकंठ में बन रही बहुमंजिला पार्किंग की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में धीरेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव आवास, डीपी सिंह, अपर आयुक्त हुडा, बीरेन्द्र प्रसाद भट्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, पेयजल, सहित सभी अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

पार्किंग में 500 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था

सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ती वाहन संख्या और तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस परियोजना को स्वीकृति की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया है। प्रस्तावित पार्किंग में 300 से अधिक चारपहिया तथा 200 से अधिक दोपहिया वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था की जाएगी। इससे न केवल यातायात दबाव कम होगा, बल्कि तीर्थ सीजन के दौरान अव्यवस्था और जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। प्रस्ताव के अनुसार पार्किंग भवन में भूतल (स्टिल्ट) सहित कुल चार स्तर होंगे, जिनमें तीन फ्लोर ऊपर निर्मित किए जाएंगे। संपूर्ण ढांचा आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि भारी भीड़ के समय भी वाहनों का सुचारु संचालन संभव हो सके। लंबे समय से अव्यवस्थित पार्किंग नीलकंठ क्षेत्र की बड़ी समस्या रही है, जिससे स्थानीय व्यापार और श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता था।

02 बेड का आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र भी किया जाएगा स्थापित

विशेष रूप से इस बहुमंजिला पार्किंग परिसर में दो बेड का आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर बुजुर्गों के लिए आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। साथ ही अधिकारियों एवं राजकीय कार्मिकों के लिए प्रतीक्षालय और विश्राम कक्ष की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इस निर्माण कार्य हेतु गठित आयोजन का नियोजन विभाग की डीपीसी के माध्यम से परीक्षण किया जा चुका है। प्रशासनोपरांत स्वीकृत लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए 29 जनवरी 2026 को विभागीय व्यय समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसके क्रम में 23 फरवरी 2026 को सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में परियोजना से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन और मिशन के अनुरूप राज्य के धार्मिक स्थलों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाने की दिशा में ठोस कार्यवाही की जा रही है। नीलकंठ में प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग केवल एक आधारभूत संरचना परियोजना नहीं, बल्कि तीर्थ पर्यटन को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि तीर्थस्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात व्यवस्था, सुरक्षित पार्किंग और आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। परियोजना को तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पारदर्शिता के साथ पूर्ण की जा रही हैं। अंतिम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक अनुभव प्राप्त हो तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले।प्रशासन का मानना है कि यह परियोजना न केवल यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि तीर्थ पर्यटन को नई दिशा देने में भी सहायक सिद्ध होगी। अब सभी की निगाहें अंतिम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर टिकी हैं, जिसके उपरांत निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है।

उत्तरकाशी में जल जीवन मिशन की योजनाओं को गति देने के निर्देश

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने वन भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण और विभागीय समन्वय पर दिया जोर

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

जनपद में जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जिला मुख्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए आवश्यक वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े विभिन्न लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए, ताकि पेयजल योजनाओं का कार्य बिना किसी बाधा के शीघ्र प्रारंभ और पूर्ण किया जा सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल संस्थान सहित सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें और वन भूमि हस्तांतरण से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। यदि किसी भी स्तर पर कोई प्रशासनिक या तकनीकी समस्या सामने आती है, तो उसे तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय को अवगत कराया जाए, जिससे उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने यह भी निर्देश दिए कि वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी नियमों और मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और नियमानुसार पूरी की जाएं। इससे जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही वन भूमि संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सकेगा और आमजन को जल्द से जल्द पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी डी.पी. बलूनी, रवींद्र पुंडीर, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग विजय कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान

पथ प्रवाह, हरिद्वार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह है सपना साफ स्वच्छ हो हरिद्वार अपना के संकल्प को साकार करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चमाचम सड़क सफाई अभियान जनपद हरिद्वार में कल 21 फरवरी, 2026 से 03 मार्च, 2026 तक व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 'मेरा घर, मेरी सड़क' थीम पर विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं । उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं धरातल पर मानटरिंग करते हुए अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नामित किए गए नोडल अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर चमाचम सड़क सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम हरिद्वार की टीम द्वारा ललतारों पुल के पास तथा नगर निगम रूड़की की टीम द्वारा नगर निगम क्षेत्र रूड़की तथा नगर पंचायत झबरेडा व नगर पंचायत सुल्तानपुर व नगर पालिका मंगलौर द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के मुख्य सड़क मार्ग व आसपास क्षेत्रांतर्गत चमाचम सड़क अभियान चलाया गया। बी एच ई एल द्वारा चौराहा सेक्टर 4 से लेकर सेक्टर 6 स्थित डिस्पेंसरी तक सड़क एवं आसपास के क्षेत्र में सफाई कार्य कराया गया। सिडकुल द्वारा भी सिडकुल क्षेत्रांतर्गत सफाई अभियान चलाया गया। विकास खंड रूड़की एवं खानपुर क्षेत्रांतर्गत चमाचम सड़क सफाई अभियान चलाया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी चमाचम सड़क सफाई अभियान चलाया गया।

विभागीय कार्यप्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेशन हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य ने सोमवार को विभागीय कार्यप्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभावी समावेशन को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। जिला सभागार में आयोजित कार्यशाला के पहले दिन 34 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जबकि दूसरे दिन कल विकास भवन सभागार में 36 विभागों के अधिकारियों एवं कार्मिको को आर्टिफिशियल इंटलीजेंस के समावेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला में अभिधेय के एडवाइजर विनीत ने एआई तकनीक चैट जीपीटी,गामा आदि के माध्यम से कार्यालयी पत्राचार के मसौदे तैयार करना,डेटा संकलन एवं विश्लेषण,अभिलेख प्रबंधन,जन शिकायतों की मॉनिटरिंग,रिपोर्टिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण,निर्णय प्रक्रिया को सुदृढ़ करना तथा नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने एआई का उपयोग विभागीय सुरक्षा और आकंड़ों को ध्यान में रखते हुए करने की सलाह दी गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गहनता से प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए तथा जहां शंका हो उसका अवश्य समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक के उपयोग से जहां प्रशासनिक कार्यों में गति,पारदर्शिता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा वहीं नागरिकों को अधिक प्रभावी और त्वरित सेवाएं भी उपलब्ध होगी। कार्यशाला में एडीएम मुक्ता मिश्र,एसडीएम शालिनी नेगी,जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दूल गुसाईं सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने न्यूज24 को कहा अलविदा

पथ प्रवाह, नई दिल्ली।

देश में अपनी बेबाक और निर्भीक पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने मीडिया संस्थान न्यूज24 से इस्तीफा दे दिया है। करीब 15 वर्षों तक संस्थान से जुड़े रहे मिश्रा ने भावुक शब्दों में अपने इस लंबे सफर को विराम दिया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में उन्होंने पत्रकारिता के दौरान झेले गए अनुभवों, आरोपों और मानसिक संघर्षों को खुलकर सामने रखा। उन्होंने लिखा कि '12 घंटे पहले अच्छा पत्रकार और 12 घंटे बाद घटिया पत्रकार' बना दिया जाना आज के दौर की विडंबना है।

'सच बोलना आसान नहीं' – प्रभाकर मिश्रा

प्रभाकर मिश्रा ने अपने संदेश में कहा कि सच के साथ खड़े रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि अपनी रिपोर्टिंग के कारण उन्हें कई तरह के विशेषणों से नवाजा गया। कभी उन्हें जातिवादी कहा गया, कभी मनुवादी, तो कभी उनके नाम के साथ 'मदनी' और 'खान' जैसे शब्द जोड़कर संबोधित किया गया।

उन्होंने लिखा कि कई बार उनके ब्राह्मण होने पर सवाल उठाए गए तो कई बार उनके हिंदू होने पर भी प्रश्नचिह्न लगाया गया। सार्वजनिक मंचों पर उन्हें अपमानजनक संबोधन दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पत्रकारिता की दिशा नहीं बदली।

किसान आंदोलन से लेकर यूजीसी कानून तक रखी बेबाक राय

प्रभाकर मिश्रा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग की। उन्होंने किसान कानूनों के विरोध पर कहा कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे थे, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद की आवश्यकता पर बल दे रहे थे।

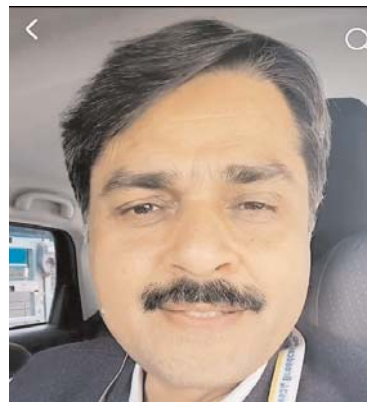

इसी प्रकार यूजीसी कानून पर भी उन्होंने संभावित सामाजिक विभाजन की आशंका जताई थी। उनका मानना था कि किसी भी कानून का प्रभाव समाज में सौहार्द और समरसता को ध्यान में रखकर परखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा कुछ मामलों में दखल दिए जाने से उनकी चिंताओं को बल मिला।

फिल्म विवाद और जातीय पहचान पर उठा विवाद

एक फिल्म के नाम में जातिसूचक शब्द के प्रयोग का विरोध करने पर भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि विरोध के आधार पर उन्हें उनकी जाति से जोड़ा गया और विरोधाभासी तरीके से कभी उन्हें 'मियां' तो कभी 'मनुवादी' कहा गया। उनका कहना है कि एक ही व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग खांचों में बांटना आज की सामाजिक मानसिकता को दर्शाता है।

'मेरा सच, आपका सच अलग हो सकता है'

अपने संदेश के अंत में उन्होंने लिखा, 'यह मेरा सच है, हो सकता है आपका सच न हो। लेकिन मेरा सच काफी हद तक सच होता है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि वे आगे भी सच को सच कहने से पीछे नहीं हटेंगे। इस्तीफे के साथ उन्होंने कहा कि अब वे अपना आई कार्ड जमा कर देंगे – 'नो मोर 24' – लेकिन उनकी पत्रकारिता की यात्रा जारी रहेगी।

पत्रकारिता जगत में चर्चा

प्रभाकर कुमार मिश्रा के इस्तीफे के बाद मीडिया जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। 15 वर्षों का उनका सफर कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों और बहसों का साक्षी रहा। अब यह देखना होगा कि उनकी अगली पारी किस मंच से शुरू होती है।

एक नजर

सीडीओ ने पशु सखियों को मोबाइल फोन देकर बढ़ाया उत्साह

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जनपद हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना के विभिन्न घटकों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक के उपरांत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बहादराबाद विकासखंड के श्रद्धा सीएलएफ के अंतर्गत कार्यरत पशु सखियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए। इस अवसर पर पशु सखियों को निर्देशित किया गया कि वे पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ नियमित समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से कार्य सुनिश्चित करें, जिससे पशुपालन गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी द्वारा परियोजना के समस्त कंपोनेंट्स पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। कुछ घटकों में अपेक्षित प्रगति न होने पर संबंधित विकासखंड स्तरीय स्टाफ को चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यदि कार्यों की प्रगति में शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में परियोजना निदेशक / सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलिनीत घिल्डियाल, जिला परियोजना प्रबंधक संजय कुमार सक्सेना सहित समस्त सहायक प्रबंधक एवं विकासखंड स्तरीय स्टाफ उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण आजीविका संवर्धन को और अधिक सशक्त बनाना रहा।

कनखल क्षेत्र में 35 लोगों का वेरिफिकेशन, 30 हजार के कोर्ट चालान

किरायेदार और घरेलू नौकरों का सत्यापन न कराने पर मकान मालिकों पर कार्रवाई

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिले में बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों और घरेलू नौकरों के सत्यापन को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत थाना कनखल पुलिस ने सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाकर कुल 35 व्यक्तियों का सत्यापन किया। प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संदेश नगर सहित अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर किरायेदारों, घरेलू नौकरों, कबाड़ियों और बाहरी व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान बिना सत्यापन के किरायेदार और बाहरी व्यक्तियों को रखने वाले तीन मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 83 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपये के कोर्ट चालान किए गए। कुल 30 हजार रुपये के चालान की रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जा रही है। इसके अलावा मौके पर पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत तीन व्यक्तियों के चालान भी किए गए, जिनसे कुल 1500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मकान मालिकों को अपने किरायेदारों और घरेलू नौकरों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने के निर्देश दिए।

एसएसपी मंजूनाथ टीसी की पुलिस टीम ने 36 लाख की स्मैक के साथ दबोचा तस्कर

बनभूलपुरा क्षेत्र में स्ट्रल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, नवंबर से अब तक 55 तस्करों पर शिकंजा

पथ प्रवाह, नैनीताल।

जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ मंजूनाथ टीसी के निर्देश में बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने लगभग 36 लाख रुपये कीमत की 121 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राज्य सरकार के 'ड्रग फ्री देवभूमि मिशन' को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 22 फरवरी 2026 को हल्द्वानी के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल और क्षेत्राधिकारी अमित कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में बनभूलपुरा क्षेत्र में गौला बाईपास रोड पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से 121 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद उमेर (24 वर्ष), निवासी अजीज गली, थाना बहेड़ी, जिला बरेली (वर्तमान निवासी टांडा, शेखपुरा) के रूप में हुई है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली बनभूलपुरा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से स्मैक के स्रोत और उसके नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसके आधार पर पुलिस अन्य तस्करों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

पुलिस टीम में उ0नि0 मनोज यादव (कोतवाली बनभूलपुरा), कानि0 दिलशाद अहमद (कोतवाली बनभूलपुरा), कानि0 भूपेन्द्र जेष्ठा, कानि0 संतोष बिष्ट शामिल रहे।

नैनीताल पुलिस का नशे पर प्रहार

एसएसपी डॉ मंजूनाथ टी0सी0 के नेतृत्व में जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार प्रभावी रूप से जारी है। नवंबर 2025 से अब तक पुलिस ने 55 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 44 मुकदमे दर्ज किए हैं। इस दौरान पुलिस ने 7.96 किलोग्राम चरस, 768.32 ग्राम स्मैक, 83 किलोग्राम गांजा, 180 नशीली गोलियां, 24 कैप्सूल और 993 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं, जो पुलिस की सक्रियता और सख्त रुख को दर्शाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस को सफलता मिली है। रामनगर में एक तस्कर को 9.84 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि लालकुआं में दो आरोपियों को 7.68 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एसएसपी डॉ0 मंजूनाथ टी0सी0 ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और इस अवैध धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का लक्ष्य जिले को पूरी तरह नशामुक्त बनाना है। इस सफल कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 2000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा भी की गई है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का एसएसपी ने लिया जायजा

सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीवी ग्रिड और एंटी-सबोटाज चेकिंग को और मजबूत करने के निर्देश

पथ प्रवाह, नैनीताल।

जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 मंजूनाथ टी0सी0 के निर्देशन में उच्च संवेदनशील स्थलों पर लगातार निगरानी और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसएसपी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल परिसर की समग्र सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

डॉ0 मंजूनाथ टी0सी0 के निर्देश पर एसपी नैनीताल डॉ0 जगदीश चंद्र के पर्यवेक्षण में मुख्य सुरक्षा अधिकारी राकेश बिष्ट, प्रभारी निरीक्षक मल्लीताल, बीडीएस एवं डॉग स्क्वॉड सहित पुलिस टीमों द्वारा न्यायालय परिसर में लगातार एंटी-सबोटाज चेकिंग और फ्रिस्किंग की जा रही है। परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति-अधिवक्ता, वादकारी, अधिकारी एवं कर्मचारियों-पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सभी प्रवेश द्वारों और बैरियरों पर तैनात पुलिस बल की

कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए श्रेणीवार सुव्यवस्थित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि सुरक्षा के साथ-साथ सुगम आवागमन भी बना रहे।

इसके अतिरिक्त सुरक्षा ऑडिट टीम को एक उच्चीकृत सिक्योरिटी स्कीम तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिसे शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। प्रभावी सीसीटीवी ग्रिड तैयार कर कैमरों की समुचित मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया। एसएसपी ने न्यायालय परिसर में तैनात क्यूआरटी, वायरलेस, चौकी, फायर सर्विस, बीडीएस तथा अन्य सुरक्षा इकाइयों की नफरी और संसाधनों का भी आकलन किया। सुरक्षा ऑडिट समिति को समग्र कार्ययोजना बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com